

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 578वीं बैठक दिनांक 16/06/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :—

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :—

1. **Case No 8148/2021 M/s Siyaram Stone Crusher, Partner, Shri Pramod Sahu, R/o, Behind Iron Majid, Bus Stand Chatarpur, Dist. Chhatarpur, MP - 471301 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (50000 cum per annum) (Khasra No. 1456/3), Village - Sarani, Tehsil - Chhatarpur, Dist. Chhatarpur (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1456/3), Village - Sarani, Tehsil - Chhatarpur, Dist. Chhatarpur (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 479वीं दिनांक 11/02/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 16/06/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र दक्षिण की ओर से खुदा हुआ है, तत्संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया है कि पूर्व लीजधारक श्री अभियंत सिंह गौण द्वारा इस क्षेत्र में खनन कार्य किया गया था तथा यह खदान

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

अप्रैल, 2020 में मुझे हस्तांतरित होकर एलओआई जारी हुआ है तथा इसका विवरण अनुमोदित माइन प्लॉन तथा सरफेस मैप में ओल्डपिट के रूप में दर्शाया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के पश्चिम भाग से 100 मीटर दूरी पर प्राकृतिक नाला निकल रहा है, जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि गारलैन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किया गया है तथा सेटलड वाटर का निस्तारण किया जायेगा। प्रकरण के गूगल इमेज के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि लीज के उत्तरी-पश्चिमी भाग से एक कच्चा रास्ता जा रहा है जिसे हेतु परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि यह शासकीय भूमि है तथा कई वर्षों से खनन कार्य न होने के कारण समीप में स्थित एक अन्य खदान द्वारा आवागमन के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। रास्ते का जो भाग हमारी लीज से होकर गुजर रहा है, वह 7.5 मीटर के बैरियर जोन से डायवर्ट करा जायेगा तथा उस हिस्से को जहाँ पर पेड़ हैं, वह नॉन माईनिंग जोन (0.10 हे. तथा 0.32 हे.) के छोड़ा गया है जिसका विवरण प्रस्तुतीकरण में दिया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान मिनरल इवेक्वेशन रोड पर जल छिड़काव तथा क्लेशर में जल छिड़काव के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी. में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग (मफल ब्लास्टिंग) की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा तथा क्लेशर खनन क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ परियोजना प्रस्तावक का शपथ-पत्र की उनके द्वारा कोई खनन कार्य नहीं किया गया है।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी.।
- ✓ खनिज परिवहन हेतु 20 टन के ट्रक क्षमता के साथ विवरण।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 16/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन— 50000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में क्वीटल राशि रु.12.01 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु.05.91 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख :-

क्रं.	जन सुनवाई आधारित सीईआर गतिविधियां	राशि रु. में
01	सरानी गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पोर्टेबल ईसीजी मशीन	50,000 /—

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 जून 2022

	का वितरण।	
02	सरानी गांव के प्राथमिक विद्यालय के समस्त छात्रों में कपड़े के बैग और बोटल का वितरण।	30,000 /—
योग		80,000 /—

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमैर, चिरौल, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1800
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	150
3	तन्देरा व सरानी ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, आम, अमरुद, कटल अन्य फलदार प्रजातियाँ।	2750
4	सरानी गांव के विद्यालय में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर।	100
कुल			4800

- 2. Case No 7474/2020 Shri Shankar Kol S/o Shri Shivdas Kol, Village - Akauna, Post - Aber, Tehsil - Rampur Baghelan, Dist Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.619 ha. (15000 cum per annum) (Khasra No. 1180/1 Gha), Village - Mudgudi, Tehsil - Manpur, Dist. Umariya (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1180/1 Gha), Village - Mudgudi, Tehsil - Manpur, Dist. Umariya (MP) 1.619 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 459वीं दिनांक 23/09/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 16/06/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र के दक्षिण-पूर्वी भाग से 200 मीटर दूरी पर जल रोकने की संरचना है तथा दक्षिण दिशा में 50 मीटर की दूरी पर एक मौसमी नाला स्थित है, जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुरानी माइंड आऊटपिट है, जिसमें पानी भरा हुआ है तथा हमारे द्वारा गारलेंन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किया गया है तथा सेटलड वाटर का निस्तारण किया जायेगा। इसी प्रकार लीज के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र की ओर लगभग 250 मीटर की दूरी पर एक पक्की रोड़ जा रही है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान जल छिड़काव के कार्य, धूल की समस्या एवं वाहनों की नियंत्रित गति संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी. में शामिल किया गया है। जन सुनवाई के दौरान ब्लास्टिंग से संबंधित मुद्दों के बारे में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा धूल नियंत्रण हेतु खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि जारी एकल प्रमाण-पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आवेदित स्थल अधिसूचित ईको सेंसेटिव जोन कितनी दूरी पर है, अतः उप संचालक, बौधवगढ़ टाईगर रिजर्व से जानकारी प्राप्त की जाये। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ उप संचालक, बौधवगढ़ टाईगर रिजर्व से प्रमाण-पत्र कि आवेदित स्थल अधिसूचित ईको सेंसेटिव जोन से बाहर है।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. योजना।
- ✓ वन्यप्राणियों से सुरक्षा की दृष्टि से ई.एम.पी. में गेमप्रूफ चैनलिंग फेंसिंग (2.10 मीटर ऊँची) का प्रस्ताव।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. योजना।

3. Case No 6769/2020 M/s R.K.Stone Company, Partner Shri Aasif Khan, Ward No. 08, Khudwari Mohalla, Barod Road, Tehsil - Alote, Dist. Ratlam, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (5,044 cum per annum) (Khasra No. 385/2/2), Village - Jeevangarh, Tehsil - Alote, Dist. Ratlam (MP). EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 385/2/2), Village - Jeevangarh, Tehsil - Alote, Dist. Ratlam (MP) 1.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 422वीं दिनांक 10/02/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 16/06/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र पश्चिम दिशा में 90 मीटर दूरी पर पक्का रोड़ निकल रहा है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह ग्रामीण पक्का मार्ग है। इसी प्रकार खदान के दक्षिण दिशा में लगभग 400 मीटर की दूरी पर एक डेम है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि हमारे द्वारा गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किया गया है तथा सेटलड वाटर का निस्तारण किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान मिनरल इन्वेक्शन रोड पर जल छिड़काव, वृक्षारोपण व सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी. एवं सी.ई.आर. में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. एवं वृक्षारोपण योजना।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 16/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन- 5,044 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 06.76 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.37 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख :-

क्रं.	जन सुनवाई आधारित सीईआर गतिविधियां	राशि रु. में
01	जीवनगढ़ गांव तहसील अलोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पोर्टेबल ईसीजी मशीन का वितरण।	40,000/-
02	जीवनगढ़ गांव के प्राथमिक विद्यालय के समस्त छात्रों को टिफिन, जूते, स्कूल बैग का वितरण।	20,000/-
योग		60,000/-

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	आंवला , कस्टार, जंगल जलेबी, चिरोल, अचार ,आदि स्थानीय प्रजातियाँ।	250
2	परिवहन मार्ग	शीशम, अमलतास, जामुन, चिरोल, करंज, स्थानीय प्रजातियाँ	110
3	जीवनगढ़ व गुलबलोद, भवगढ़ के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	अमला, बेल, नीबू आम, सिशु, जामुन, शीशम, इमली, महुआ, अन्य फलदार प्रजातियाँ।	820
4	जीवनगढ़ गांव के विद्यालय में	अशोक, नीम, अमलतास, गुलमोहर।	20
कुल			1200

4. Case No 6770/2020 Shri Aabid Khan, Ward No. 8, Khudwari Mohalla, Barod Road, Tehsil - Alote, Dist. Ratlam, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (12,125 cum per annum) (Khasra No. 143), Village - Khamariya, Tehsil - Alote, Dist. Ratlam (MP). EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 143), Village - Khamariya, Tehsil - Alote, Dist. Ratlam (MP) 2.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 422वीं दिनांक 10/02/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 16/06/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए। इसी प्रकार खदान के दक्षिण-पश्चिमी दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक डेम है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि हमारे द्वारा गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किया गया है तथा सेटलड वाटर का निस्तारण किया

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान खदान से 800 मीटर की दूरी पर गौशाला होने के कारण गायों के चरने की समस्या संबधी तथा ग्राम पंचायत, खमरिया ने दिनांक 11/01/22 को यह प्रस्ताव पारित किया है किं खसरा क्रमांक— 04, 143, 151, 152 की भूमि को गोचर एवं गौशा के रूप में सुरक्षित रखे जाने हेतु सरंक्षित किया है, यदि पूर्व में भूमि दी गई तो उसे भी निरस्त किया जाता है ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण में पाया कि इसी खदान के पास एक अन्य प्रकरण 6769/2020 मेसर्स आर.के. स्टोन कम्पनी पार्टनर श्री आशिफ खान की जनसुनवाई भी इस खदान के साथ ही हुई थी तथा वह भी इसी खदान के पास में स्थित है, जिसमें उपरोक्त आपत्तियों/सुझाव प्राप्त नहीं हुए । लीज स्वीकृति के पूर्व ग्रामसभा अनापत्ति प्राप्त है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सरपंच द्वारा द्वेशवश उक्त प्रस्ताव पारित किया गया है जबकि पूर्व में ग्रामसभा ठहराव प्रस्ताव दिनांक 10/01/18 के द्वारा अनापत्ति प्राप्त है, उक्त अनापत्ति के आधार पर ही कार्यालय कलेक्टर द्वारा दिनांक 01/06/2018 को लीज स्वीकृत की गई । हमारी खदान से गौशाला की दूरी लगभग 800 मीटर है तथा 500 मीटर की क्षेत्र में 05 अन्य खदानें कार्यरत हैं यदि इस ग्राम पंचायत, खमरिया के प्रस्ताव दिनांक 11/01/22 आधार पर मेरी खदान निरस्त की जाती है तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर सभी उपरोक्त खदानों को निरस्त की जानी चाहिए । प्रस्तावित खनन क्षेत्र गौशाला करीब 800 मीटर की दूरी पर है तथा 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें हैं । हमारे द्वारा ई.एम.पी. में गौशाला के पास स्थित शासकीय भूमि में चरनोई भूमि के विकास हेतु रु. 01.00 लाख का प्रावधान किया गया है । समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक के कथन अनुसार आंवटित स्थल से गौशाला करीब 800 मीटर दूर है तथा आस-पास शासकीय भूमि उपलब्ध है जिसमें परियोजना प्रस्तावक ने चरनोई भूमि के विकास हेतु रु. 01.00 लाख का प्रावधान किया गया है ।

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. एवं वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 16/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन-12,125_मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु.09.12 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.87 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख :-

क्रं.	जन सुनवाई आधारित सीईआर गतिविधियां	राशि रु. में
-------	-----------------------------------	--------------

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 जून 2022

01	ग्राम खमरिया में गौशाला के लिए चराई भूमि का विकास किया जायेगा।	50,000 /—
02	ग्राम खमरिया के प्राथमिक विद्यालय में समस्त विद्यार्थियों को टिफिन व पानी की बोतल का वितरण किया जायेगा।	10,000 /—
(आगामी एक वर्ष तक) योग		60,000 /—

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1900 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	आंवला , कस्टार, जंगल जेलबी, चिरोल आदि स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
2	परिवहन मार्ग	शीशम, अमलतास, जामुन, करंज, चिरोल स्थानीय प्रजातियाँ,	400
3	खमरिया ग्रामवासियों में वितरण हेतु	अमला, बेल, नीबू आम, सिस्सू, जामुन, इमली, महुआ, अन्य फलदार प्रजातियां।	240
4	खमरिया गांव के विद्यालय में	कचनार, आम, सीता अशोक, नीम, गुलमोहर।	10
5	गौ शाला में	शीशम, अमलतास, जामुन, करंज स्थानीय प्रजातियाँ,	250
कुल			1900

- 5. Case No 7555/2020 M/s Jindal Earth Mines, R/o 55, Dashahara Maidan, Dist. Ujjain, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.460 ha. (60000 cum per annum) (Khasra No. 347), Village - Pingleshwar, Tehsil - Ujjain, Dist. Ujjain (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 347), Village - Pingleshwar, Tehsil - Ujjain, Dist. Ujjain (MP) 1.460 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 460वीं दिनांक 24/09/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज दिनांक 29/05/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

आज दिनांक 16/06/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सकसेना उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र में 03 पेड़ लगे हैं जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ये सभी पेड़ बैरियर जोन में लगे हैं, अतः काटे जाने का प्रस्ताव नहीं है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र के दक्षिण भाग से 50 मीटर की दूरी पर एच.टी. लाईन तथा उत्तर भाग से 140 मीटर दूरी पर रेल्वे लाईन है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के अनुसार 100 मीटर की दूरी रेल्वे लाईन से छोड़ी जानी होती है अतः वे रेल्वे लाईन से सुरक्षित दूरी पर हैं। समिति ने चर्चानुसार यह अनुशंसा की कि ब्लैस्टिंग के दौरान फ्लाइंग उड़कर रेल की पटरी तक न जाये, इसलिए खनन कार्य दक्षिण से उत्तर की ओर किया जाये तथा उत्तरीय क्षेत्र में 4 मीटर की प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो की द्वारा रोड़ पर पानी का छिड़काव, खदान की तार फेंसिंग, ब्लैस्टिंग के दौरान सावधानी, परिवहन मार्ग की मरम्मत तथा स्कूल में खेल कूद हेतु मैदान तथा वृक्षारोपण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी. एवं सी.ई.आर. में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन हेतु कंट्रोल ब्लैस्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र की लीज में विद्यमान पेड़ो को नही काटा जायेगा।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 16/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 60000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 07.95 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 04.11 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.80 लाख :-

क्रं.	जन सुनवाई आधारित सीईआर गतिविधियां	राशि रु. में
1	पिंगलेशवर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल बेड दिए जायेंगे। (20) ,000 X 3) तथा स्वास्थ्य केंद्र में अधिकारी से परामर्श करके चिकित्सीय उपकरण दिया जायेगा (20,000)	80, 000
2	पिंगलेशवर गांव में उचित स्थानों पर 20 कचरा पात्र रखे जायेंगे तथा समय . सफाई का ध्यान रखा जायेगा - समय पर उनकी साफ	30,000
3	पिंगलेशवर गांव में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जायेगा।	70, 000
योग		1,80,00

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1850 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (7.50) मीटर बेरियर जोन में तीन लाइनों में किया जायेगा)	नीम, सीताफल, पीपल , कचनार, आंवला, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू आदि।	450
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड) 10 00 मी (के दोनों ओर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, अशोक आदि	500
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	900
कुल			1850

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 जून 2022

6. Case No 9210/2022 Shri Rajesh Pratap Singh Lessee, Village - Chakrahan Tola, Naigarhi, Tehsil - Naigarhi, Dist. Rewa, MP - 486340, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (9872 Cum per annum) (Khasra No. 10/3), Village - Pathrauda Kalan, Tehsil - Naigarhi, Dist. Rewa (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 10/3), Village - Pathrauda Kalan, Tehsil - Naigarhi, Dist. Rewa (MP) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 16/06/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 962 दिनांक 20/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम दिशा में 90 मीटर पर नदी है तथा पूर्व दिशा में 425 मीटर पर जल निकाय स्थित है अतः नदी से 10-10 मीटर का सेटबैक छोड़ा जाना होगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नदी एवं जलीय निकाय के कारण गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किये गये हैं तथा सेटलिंग के पश्चात् ही जल का निस्तारण किया जावेगा। इसी प्रकार खदान क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम दिशा में 440 मीटर दक्षिण-पश्चिम दिशा में 370 मीटर पर आबादी एवं पश्चिम दिशा में 485 मीटर पर पक्की रोड है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ नॉन माईनिंग क्षेत्र (लीज के उत्तर-पश्चिम भाग) दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 16/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन -9872 मी³ प्रति वर्ष।

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु.11.49 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.96 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम पथरौडा कलां के ग्राम पंचायत भवन में एक कम्प्यूटर, प्रिंटर, टेबल के साथ	60,000
ग्राम पथरौडा कलां के ग्राम पंचायत भवन एवं ऑगनवाडी में 20 छायादार वृक्षों (कदम्ब, कचनार, करंज, बहुनिया एवं अन्य प्रजातियों) को ट्री गार्ड के साथ लगाना	10000
योग	70,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	आंवला, सिस्सू, नीम, पीपल, करंज, खमेर, चिरोल, सीताफल, कुम्भी, बीजा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	700
2	परिवहन मार्ग तक (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	कदम्ब, नीम, पीपल, आम, चिरोल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आंवला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	200
4.	अष्टभुजा माता मंदिर के आस - पास	कदम्ब, नीम, पीपल, कचनार, कुम्भी, आम, आंवला, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
कुल वृक्षारोपण			1200

7. Case No 9214/2022 Smt. Sunita Meda, Owner, 88/1, Bakhtawar Road, Tehsil & Dist. Dhar, MP - 454001, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 3.30 ha. (15000 Cum per annum) (Khasra No. 496/3), Village - Bodla, Tehsil - Sardarpur, Dist. Dhar (MP)

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 496/3), Village - Bodla, Tehsil - Sardarpur, Dist. Dhar (MP) 3.30 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

आज दिनांक 16/06/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 468 दिनांक 29/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 75 मीटर पर हाईवे है तथा 08 मीटर पर एक पक्का रोड़ है, अतः हाईवे से 25 मीटर तथा पक्के रोड़ से 42 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पक्का रोड़ वर्तमान में उपयोग में नहीं है तथा हाईवे के निर्माण के दौरान उसे वाई पास हेतु बनाया गया था इसलिए इस रोड़ से सेट बैक छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार खदान के पूर्व दिशा में 10 मीटर पर मौसमी नाला है, अतः 40 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाये। खदान के उत्तर-पूर्व दिशा में 50 मीटर पर जल रोकने की संरचना है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जलीय निकाय के कारण गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किये गये हैं तथा सेटलिंग के पश्चात् ही जल का निस्तारण किया जावेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण मुरुम का है, जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ खदान के दक्षिण दिशा में 75 मीटर पर हाईवे है अतः हाईवे से 25 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाये। इसी प्रकार खदान के पूर्व दिशा में 10 मीटर पर मौसमी नाला है, अतः 40 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाये तथा नॉन माईनिंग क्षेत्र दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी./वृक्षारोपण/सीईआर योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 16/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मुरुम - 15000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.87 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.95 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.30 लाख :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
गांव बोदला में आंगनवाडी में बच्चों के लिए पोषहार का वितरण किया जावेगा	50ए 000

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

ग्राम बोदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अधिकारी से परामर्श करके चिकित्सीय उपकरण दिया जायेगा	80ए 000
योग	1,30, 000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3900 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में तीन लाइनों में किया जायेगा)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू, सीताफल आदि।	1200
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड के दोनों ओर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	500
3.	सेट बैक में लगाए जाने वाले पौधे	नीम, बबूल पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	520
4.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	1680
कुल वृक्षारोपण			3900

8. **Case No 9215/2022 Shri Nilesh Raghuvanshi, Owner, Pahadsinghpura, Raghuvanshi Path, Mangal Bhawan, Dist. Khargone, MP - 451001 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (20000 Cum per annum) (Khasra No. 07), Village - Mominpura, Tehsil - Khargone, Dist. Khargone (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 07), Village - Mominpura, Tehsil - Khargone, Dist. Khargone (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 16/06/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 7687 दिनांक 27/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार प्रस्तावित

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

खदान को मिलाकर कुल रकबा 4.00 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान का अधिकांश भाग खुदा हुआ है तथा उत्तरी एवं पूर्वी सीमा में पक्के मकान एवं शेड दिखाई दे रहे हैं एवं लीज के अंदर कुछ पेड़ लगे हुए हैं। इसी प्रकार एक कच्चा रोड़ लीज के अंदर से उत्तरी दिशा से दक्षिण दिशा में जा रहा है तथा दक्षिण दिशा में 10 मीटर पर पक्का रोड़ है।

समिति ने पाया कि लीज के पश्चिम एवं पूर्व दिशा में काफी खदानें (प्रश्नाधीन खदान के अतिरिक्त 04 और खदानें) दिखाई दे रही हैं तथा कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 7687 दिनांक 27/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में सिर्फ 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी है तथा 01 खदान की अवधि समाप्त हो चुकी है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :—

- ✓ खनिज अधिकारी का स्पष्टीकरण की प्रश्नाधीन खदान के 500 मीटर की परिधि में कुल कितनी खदानें स्वीकृत/संचालित हैं क्योंकि लीज के पश्चिम एवं पूर्व दिशा में काफी खदानें (प्रश्नाधीन खदान के अतिरिक्त 04 और खदानें) दिखाई दे रही हैं अतः इन खदानों की स्थिति स्पष्ट की जाये साथ ही खनन क्षेत्र बीच में से खुदा हुआ है के संदर्भ में खनिज अधिकारी द्वारा जानकारी।
- ✓ खदान के उत्तरी एवं पूर्वी सीमा में पक्के मकान एवं शेड दिखाई दे रहे हैं तथा एक कच्चा रोड़ लीज के अंदर से उत्तरी दिशा से दक्षिण दिशा में जा रहा है एवं दक्षिण दिशा में 10 मीटर पर पक्का रोड़ है अतः इनके संरक्षण की योजना।
- ✓ लीज के अंदर कुछ पेड़ लगे हुए हैं अतः ट्री इन्वेन्ट्री मय प्रजाति का नाम, ऊँचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी./वृक्षारोपण/सीईआर योजना।

9. Case No 9220/2022 M/s Devi Construction, Prop., Shri Jitendra Kumar Pateria, Village - Berkheri, Post - Sahawan, Tehsil - Banda, Dist. Sagar, MP - 470337, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 564), Village - Berkheri, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 564), Village - Berkheri, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

आज दिनांक 16/06/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 966 दिनांक 25/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 170 मीटर एवं पश्चिम दिशा में 230 मीटर पर पक्की रोड़ है। इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम दिशा में 280 मीटर पर स्कैटर्ड आवास हैं। आवंटित क्षेत्र प्राकृतिक जल धारा से निर्मित गुली पर स्थित है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ नॉन माईनिंग क्षेत्र (लीज के दक्षिणी-पूर्वी भाग) दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी./वृक्षारोपण/सीईआर योजना।

Discussion on Query Reply submitted by PP or file received from SEIAA

10. Case No 9193/2022 Shri Jitendra Yadav, Owner, A-2, Mandakini Block, Kevihgar Line 1, Batalian, Dist. Indore, MP - 453111 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 1.20 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 178/228/1), Village – Alwasa Tehsil Mhow, Dist. Indore (MP)

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 178/228/1), Village - Alwasa, Tehsil - Hatod, Dist. Indore (MP) 1.20 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 122 दिनांक 10/01/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई (01 उत्खनन पट्टा स्वीकृत जो मा. न्यायालय के

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

आदेश से शिथिल अवस्था में) खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर के अंदर एक उत्खनिपट्टा स्वीकृत था, जो कि वर्तमान में मा. उच्च न्यायालय के आदेश पालन में शिथिल अवस्था में है। समिति को उपरोक्त एकल प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव इस खदान पर भी लागू है या नहीं। अतः इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक से मा. उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के बारे में जानकारी चाही गई तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अभी उनके पास इस संदर्भ में अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः जानकारी प्रदाय करने हेतु 10 दिन का समय दिया जाये। अतः समिति की अनुशंसा है कि मा. उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण की अद्यतन वस्तुस्थिति से 10 दिनों में अवगत कराया जाये, तत्पश्चात् प्रकरण विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 16/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मरुम - 10000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. लाख :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम दतोदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 फोल्डेबल व्हील चेयर्स उपलब्ध कराई जाएंगी।	15,000/-
ग्राम दतोदा के आंगनवाड़ी केंद्र में भोजन बनाने, खाने एवं रखने हेतु बर्तन एवं बच्चों के लिए खिलोने उपलब्ध करवाए जावेंगे।	15,00/-
योग	30,000 / -

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
-----	---	---------------------	---------------------

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, करंज आदि।	1220
2	परिवहन मार्ग तक (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, करंज, बरगद, चिरोल, नीम, सिस्सू आदि।	280
3	ग्राम दतोदा के प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा, मोलश्री, संतरा, पपीता, आम, इमली, मुनगा, कटहल करंज, आवला आदि।	50
4.	ग्राम दतोदा के शासकीय विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा, मोलश्री, कचनार, सप्तपर्णी, नीम, करंज आदि।	150
5.	ग्राम के ग्रामीणों में वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आम, जामुन, अमरुद, आमला, अनार, इमली, निम्बू, कटहल आदि।	730
कुल वृक्षारोपण			2430

परियोजना प्रस्तावक ने ऑन लाईन जबाब 05/6/22 को प्रस्तुत किया एवं प्रकरण 16/6/22 को प्रस्तावित बैठक में सुनवाई हेतु रखा गया ।

प्रकरण आज दिनांक 16/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

11. Case No 9138/2022 Shri Kamran Khan, Owner, 105, Badribagh Colony, Manik Bagh Road, Dist. Indore, MP - 454001, Prior Environment Clearance for Stone & M-sand Quarry in an area of 4.0 ha. (Stone - 25000 cum per annum, M-sand - 75000 cum per annum) (Khasra No. 181/2), Village - Nimola, Tehsil - Dharampuri, Dist. Dhar (MP)

This is case of Stone & M-sand Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 181/2), Village - Nimola, Tehsil - Dharampuri, Dist. Dhar (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

आज दिनांक 11/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल-पत्र क्रमांक 466 दिनांक 29/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान सिल के दक्षिण दिशा में 165 मीटर पर नर्मदा नदी है । लीज क्षेत्र 18 पेड़ है जो काटे जायेंगे एवं उनके एवज में 180 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ फार्म-2 में लैंड फारेस्ट लैंड दिखाई है, इसके संबंध में स्थिति स्पष्ट करें ।
- ✓ प्रस्तावित एम-सेंड प्लांट नर्मदा नदी के एच.एफ.एल. से कितना दूर है, की सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित जानकारी प्रस्तुत करें।
- ✓ एम-सेंड प्लांट के ले-आउट को सरफेस मैप पर दिखाया जाये ।
- ✓ एम-सेंड प्लांट से उत्पन्न होने वाले दूषित जल के शोधन की व्यवस्था तथा उत्पन्न होने वाले सिल्ट के अपवहन का विवरण प्रस्तुत करें ।
- ✓ भूमि क्षरण रोकने हेतु लीज क्षेत्र के नीचे (नर्मदा नदी की ओर) खाली पड़ी शासकीय भूमि में बैम्बू के सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
- ✓ चूंकि लीज क्षेत्र नर्मदा नदी के पास (लगभग 165 मीटर दूर) स्थित है, अतः बारिश के पानी के उचित निस्तारण की व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करें ।
- ✓ प्रस्तावित किये गये गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के डायमेंशन तथा उसमें स्टोन पिचिंग का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण एवं ई.एम.पी. योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.एस.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक ने ऑन लाईन जबाब 09/6/22 को प्रस्तुत किया एवं प्रकरण 16/6/22 को प्रस्तावित बैठक में सुनवाई हेतु रखा गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी का प्रस्तुतीकरण किया गया तथा प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि समिति द्वारा पूर्व में “प्रस्तावित एम-सेंड प्लांट नर्मदा नदी के एच.एफ.एल. से कितना दूर है, की सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित जानकारी चाही गई थी” किन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा एच.एफ.एल./रिवर फ्लड प्लेन के स्थान पर एफ.आर.एल की

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 जून 2022

जानकारी दी गई है जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आफिस मेमोरेण्डम दिनांक 14/2/22 (*"Industries shall not be located within the river flood plain corresponding to one in 25 years flood. As certified by concerned District Magistrate/Executive Engineer from state water resource Deptt., or any other officer authorized by State Govt. for this purpose."*) के अनुसार समाधान कारक नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक को पुनः उपरोक्तानुसार जानकारी 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।

12. Case No. - 5557/2017 Shri Jaikishan Jakhodiya, M/s Jakhodia Minerals, Jakhodia Group 184, Samta Colony, Raipur, (C.G.) Prior Environment Clearance for Capacity Expansion in Iron Ore Beneficiation Plant of M/s Jakhodia Minerals, at Khasra No. 75 & 85 Village - Dhamki, Tehsil - Sihora, Distt. - Jabalpur, (M.P.) Existing Capacity – 19,800 TPA, Proposed Input – 3,00,000 TPA Output – 2,10,000 TPA. Cat. 2(b) Mineral Benification Projects. EIA Consultant: M/s. Creative Enviro Services, Bhopal

This is an Ore beneficiation project comprising beneficiation of Iron Ore. The project is covered under the provisions of EIA notification as item no. 2 (b), hence requires prior EC from SEIAA. It was reported that, the industry is operational with existing production capacity of 19,800 TPA and proposes an expansion in the production capacity up to – 3,00,000 TPA. Application submitted by the PP was forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 306वीं दिनांक 27/01/2018 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

PP has submitted the EIA report on line which was forwarded through SEIAA and the same was scheduled in the agenda.

The EIA was presented by the PP Shri Ashutosh Jhakodia and Env. Consultant Shri Umesh Mishra from M/s. Creative Enviro Services, Bhopal wherein PP submitted that they have obtained MoEF&CC compliance report of earlier EC conditions wherein no non compliances are reported. PP further submitted that they have obtained CTO from MPPCB for existing production of 19,800 MT/A of iron ore beneficiation. PP further submitted that now expansion in beneficiation activity is proposed from 19,800 TPA to 3,00,000 TPA for Iron Ore, Manganese Ore and Bauxite Ore through

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

physical beneficiation only and input volume shall be met through their captive mines. Total land in possession is 1.40 ha of Khasara No. 75 which has been kept for beneficiation activity. The beneficiation plant covers 750 sq. mt. Green belt has been developed with 350 within the premises. Further 0.54 ha of Khasara No. 85 is also in their possession near to existing owned land. This shall be used for tailing disposal and management. During presentation, PP submitted that this piece of land will be used for making bricks of tailing residues. Committee suggested that on remaining part of land after (leaving area for brick plant) shall be used for thick green belt development. Committee further suggested that PP shall also strengthen peripheral plantation and plantation along the transportation route and revised proposal may be submitted with commitment that entire plantation will be completed within 02 years. During discussion it was observed that details of existing machinery (plant configuration) and proposed machinery for proposed expansion is not clear hence same shall be submitted. PP informed during presentation that 200 KLD water is required which is fulfilled from their mine through pipeline. It was observed that a borewell is in existence within the plant for which committee suggested that this borewell shall only be used for drinking purpose. For disposal of tailings PP submitted that at present they are disposing these tailings mostly through brick kilns and some part through cement plants. Committee recommends that after expansion, the volume of tailings will be enhanced and thus same shall be disposed through cement plants, brick making and lastly through brick kilns manufactures. Committee also recommends that PP shall explore the possibility of making useful materials from this waste such as paved blocks for which a scientific study shall be carried out from any institute of national repute within a year and their findings shall be submitted with six monthly compliance reports. PP submitted that issues raised during public hearing were for employment, pollution due to dust and mud generation, water discharging from the plant, water crisis in the nearby places etc. PP submitted that for dust suppression they have installed sprinklers on transportation road which causes mud generation some times and have addressed all the issues in the proposed EMP & CER with budgetary allocations including budget for pucca road. Committee during deliberations suggested that the stock pile which is used in feeding to hopper for beneficiation shall always have 15-20% moisture to avoid fugitive emission of dust and stored stock pile must have minimum 15% moisture. PP submitted that “Zero Liquid Discharge” shall be maintained. After presentation and discussion PP was asked to submit response on following:

1. Revised plantation scheme as suggested by committee along with proposal for strengthening of peripheral plantation with commitment that entire plantation within the premises and site surrounding will be completed within initial 02 years.
2. Revised EMP and CER as suggested by committee.
3. Copy of leachate analysis report.
4. Details of existing machinery (plant configuration) and machinery proposed for expansion shall be submitted.
5. Commitment of PP that tailings shall be disposed through cement plants, brick making and paver blocks.
6. Commitment of PP that all internal roads and transportation roads will be made pucca.

PP vide their letter dated 06.07.2021 submitted query reply which was placed before the committee and the same found satisfactory. The EIA/EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC for Capacity Expansion in Ore Beneficiation Plant for Iron, Mn and Bauxite of M/s Jakhodia Minerals, at Khasra No. 75 & 85 Village - Dhamki, Tehsil - Sihora, Distt. - Jabalpur, (M.P.) Existing Capacity – 19,800 TPA to Proposed Input – 3,00,000 TPA Output – 2,10,000 TPA. Cat. 2(b) Mineral Benification Projects subject to the following special conditions:

“Today the case was considered and discussed by the authority. The case was recommended by SEAC for “PP vide their letter dated 06/07/21 submitted query reply which as placed before the committee and the same found satisfactory. The EIA/EMP and other submission made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC for Capacity Expansion in Ore Beneficiation Plant for Iron. Mn and Bauxite of M/s. Jakhodia Minerals Khasra No. 75 & 85 Village - Dhamki, Tehsil - Sihora, Distt. - Jabalpur, (M.P.) Existing Capacity – 19,800 TPA, Proposed Input – 3,00,000 TPA Output – 2,10,000 TPA.

- It is noted that the letter dated 06/7/21 mentioned in recommendation is not available on Parivesh Portal.
- SEAC recommendation the case for Capacity Expansin in Ore Benefication Plant for Iron, Mn and Bauzite of M/s. Jakhodia Minerals, however PP has applied only for expansion of Iron Ore benefication in Form-2 respectively.

In context of above it is decided to refer the case back to SEAC for clarification and it needed revised form-I queries reply should be submitted by PP through ADS on Parivesh Protal

प्रकरण आज दिनांक समिति के समक्ष रखा गया जिसमें समिति ने यह अनुशंसा की कि सिया से प्राप्त निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक को जानकारी ऑन लाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करने बावत् निर्देशित किया जाये ।

13.Case No 8370/2021 M/s. Hardoul Granite, Prop. Smt. Krishna Yadav W/o Shri Ashok Singh Yadav, 108, Bankers Colony, Thatipur, Dist. Gwalior, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.320 ha. (150005 cum per annum) (Khasra No. 13h), Village - Lakhanpura, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 13h), Village - Lakhanpura, Tehsil - Dabra,

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

Dist. Gwalior (MP) 2.320 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 493वीं दिनांक 23/03/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

सेक की 570वीं बैठक दिनांक 11/05/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है जिसमें पूर्व में 80,000 घनमीटर / वर्ष की क्षमता से 1,50,005 घनमीटर/वर्ष की क्षमता की जाना प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया उनके द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व की पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है, जो उनके पत्र क्रमांक 082 दिनांक 15/03/2022 द्वारा जारी किया गया है । जारी किए गए पालन प्रतिवेदन में कोई भी नॉन कम्प्लाइंस नहीं पाई गई । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा यह खदान वर्ष 2021 में पूर्व की लीजधारक से अपने नाम स्थानांतरित कराई गई है तथा उनके द्वारा अभी कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह भी बताया कि पूर्व के लीजधारक द्वारा बैरियर जोन में समुचित वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है जबकि डिया से प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार 45 वृक्ष प्रति हेक्टेयर (कम से कम 100) लगाये जाने थे, अतः उनके द्वारा लगभग 200 पेड़ों का वृक्षारोपण खनन क्षेत्र में किया गया है जिसके फोटोग्राफ्स प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न है । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के पूर्वी क्षेत्र में एक पिट है जिसमें पानी भरा है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह माइंड आऊट पिट है जिसमें से माइन प्लान के अनुसार लगभग 37,842 घनमीटर पत्थर निकाला जा चुका है तथा पूर्व के खदान मालिक द्वारा वर्ष 2017-18 में उत्खनन कार्य किया गया है एवं तत्पश्चात् खदान में कार्य बंद है । प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि खदान क्षेत्र के दक्षिण भाग से एक कच्ची रोड़ निकल रही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुतीकरण में इस कच्ची रोड़ के संरक्षण हेतु 10 मीटर का सेट-बैक (7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़कर) प्रस्तावित किया गया है तथा खनन के इस क्षेत्र में हाई डेनसिटी प्लांटेशन किया जाना प्रस्तावित किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण एवं सामाजिक कल्याण के कार्य (जैसे स्कूल में खेल सामग्री, शौचालय हेतु हेण्डपम्प वाटर टैंक, पेय जल की व्यवस्था) किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । ई.आई.ए. रिपोर्ट में उत्पादन क्षमता टन / वर्ष उल्लेखित है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह टंकण त्रुटि है, हम ई.आई.ए. रिपोर्ट सुधार कर आज प्रस्तुत कर रहे हैं । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-10(i) में परियोजना की लागत रु. 30 करोड़ दिखाई गई है, कृपया स्पष्ट करें ।
- ✓ फार्म-2 अनुसार पी.एम.-10 की वैल्यू 96 है, कृपया इसको कम करने के सुझाव प्रस्तावित करें ।
- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-32(3) के अनुसार खनन क्षेत्र में 1200 पौधे लगे हैं, कृपया स्थिति स्पष्ट करें ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 11/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

5. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन -1,50,005 मी³ प्रति वर्ष वर्ष ।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु.13.19 लाख एवं रिक्रिंग 08.63 लाख प्रति वर्ष ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.00 लाख :-

क्रं.	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
1.	ग्राम लखनपुरा के प्रथमिक विद्यालय में 01 हैण्ड पंप व 2000 लीटर ओवरहेड टैंक बनाकर शौचालय में पानी की व्यवस्था किया जायेगा तथा उचित जल चैनलाइजेशन सिस्टम के साथ ।	70,000
2.	ग्राम लखनपुरा के प्रथमिक विद्यालय में खेदकूद सामग्री का वितरण ।	20,000
3.	ग्राम लखनपुरा में मास्क एवं हैंड सेनेटाइजर का वितरण ।	10,000
4.	पोर्टेबल ई.सी.जी. मशीन, व्हील चेयर, तथा स्ट्रेचर का वितरण पी.एच. सी. लखनपुरा में किया जायेगा ।	1,00,000
योग		2,00,000
संबंधित पी.एच.सी. में पदस्थ चिकित्सक के सुझाव अनुसार उपरोक्त इवेंट्री में परिवर्तन किया जा सकेगा ।		

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण :

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 जून 2022

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	शीशम, नीम, चिरौल, पीपल, बरगद, खमैर, सीताफल, करंज, अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	2000
2.	लखनपुरा के शासकीय विद्यालय में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर।	10
3	ग्रामपंचायत लखनपुरा के ग्रामवासियों को वितरण हेतु	आवंला, आम, अमरुद, जामुन, सीताफल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	490
4.	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1500
कुल			4000

सिया ने पत्र क्रमांक 702 दिनांक 06/6/22 के माध्यम से नस्ती सेक को वापिस भेजी जिसमें यह उल्लेखित है कि "सेक की अनुशांसा अनुसार प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को फार्म-2 से संबंधित 05 बिंदु की जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया था परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम 03 बिंदुओं की जानकारी परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि परियोजना प्रस्तावक से सेक में पुनरीक्षित ई.आई.ए. रिपोर्ट ऑफ लाईन प्राप्त की गई है जो कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार नहीं है। अतः प्राधिकरण ने विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त बिंदुवार जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑन लाईन प्राप्त कर सेक द्वारा कार्यवाही अनुशांसित की जाये।

प्रकरण आज दिनांक समिति के समक्ष रखा गया जिसमें समिति ने यह अनुशांसा की कि सिया से प्राप्त निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक को जानकारी ऑन लाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करने बावत् निर्देशित किया जाये।

14. Case No 9039/2022 M/s Life Care Logistic Pvt. Ltd, Shri Vaibhav Rai, Director, 37 - 38, Lasudia Mori, Dewas Naka, A.B. Road, Dist. Indore, MP Prior Environment Clearance for Development of Commercial Warehouse at Village - Pirkaradiya, Tehsil - Sawyer, Dist. Indore, (MP) Env. Consultant M/s. Global Management And Engineering Consultants International, Jaipur (Raj.).

This is case of Prior Environment Clearance for Development of Commercial Warehouse at Village - Pirkaradiya, Tehsil - Sawyer, Dist. Indore, MP. Cat. - 8(a) Building and Construction Projects.

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

Earlier this case was scheduled in the SEAC 556th meeting dated 02.03.2022, for presentation and discussion in 556th SEAC dated 02/03/2022 wherein ToR (Violation) was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded through SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

The EIA was presented by the Mr. Sameer Khedkar PP and their Shri G.K.Mishra Env. Consultant from M/s. Global Management And Engineering Consultants International, Jaipur (Raj.), wherein PP submitted that the proposed project is a Development of Commercial Warehouse, with total plot area of 1,30,780.00 sqm., and planning area is 1,29,942.63 sqm. The proposed built-up area of the proposed project will be 56,156.00 sqm. Construction work has been completed and covered till 55% of built-up area owing to unawareness of the EIA Notification and its amendments and falls under the purview of the EIA Gazette Notification dated 08.03.2018, amending the Notification dated 14th March 2017. but actual at site presently 6 to 8 % area has been finished for working on rest covered area only prefabricated installations have been done. This report has been prepared in compliance to Gazette Notification dated 08.03.2018, amending the Notification dated 14th March 2017 including assessment on ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan.

The salient features of the project:

- The project “Development of Commercial Warehouse” located at Survey No. 53, Khasra No. 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 53/1, 53/2, 53/3, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66/1, 66/2, 67/1, 75/1, 75/2, 75/3 etc. at Village- Pirkaradiya, Tehsil- Sewer, District- Indore, Madhya Pradesh, India. Area of Project is 1,30,780.00 m² (1.30 Ha.) and it offers Warehouse-1, Warehouse-2, & Warehouse-3.
- The proponent has been constructed structure of 1 & ½ units of warehouse namely Warehouse 1 & 2. 3rd unit is not constructed or started on ground.
- Field studies has been referenced nearby project study which is almost attached to the project site for the period 1st December 2020 to 28th February 2021 (Winter Season) to determine the existing conditions of various environmental attributes.

Chronology of the Project

Application Submission to SEIAA	28-02-2022
TOR Approved by SEIAA	17-03-2022
Final EIA Report Submission to SEIAA	09-05-2022
Total Built-up Area	56,156 sqm

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

Build-up Area of Warehouse-1	20,520 sqm
Build-up Area of Warehouse-2	19,836 sqm
Build-up Area of Warehouse-3	15,800 sqm

ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN –

S. No.	Particulars	Total cost	Recurring Cost (Annual)	Remarks
1	Sewage Treatment Plant	₹ 9,40,600	₹ 1,50,000	AMC + Operator cost
2	Storm water drainage/ RWH Pits with boring / roof top channel	₹ 52,00,000	-	-
3	Solid Waste Management	₹ 1,38,000	₹ 74,000	Wastebin + Manpower
4	Environmental Monitoring	₹ 2,00,000	₹ 2,00,000	
5	DG set Stack	₹ 9,38,600	₹ 2,04,600	DG cost + permission + challan + diesel
6	Horticulture & Green Belt	₹ 2,40,000	₹ 1,50,000	Plants + Gardener
7	Fire Fighting	₹ 3,84,00,000	-	Fire Hydrants
8	Solar Energy	₹ 8,11,500	₹ 15,000	Solar Plant + AMC
9	Health, Safety & Miscellaneous	₹ 37,000	₹ 11,000	Safety Shoes + Safety Jackets + Safety Helmet + Safety Signages
10	Water supply / Tanks & Services	₹ 85,85,520	₹ 25,00,000	Borewell (Drill to Motor Fixing) + Underground Tanks + Tanker Water Cost
11	Electrical development	₹ 2,93,00,000	-	
Total		₹ 8,47,91,220	₹ 3,04,600	

REMEDIATION PLAN:

S. No.	Aspects	Amount (INR - Lakh)
1.	Capital	7.7
2.	Recurring	4.05
Total		11.75
All remediation budgets will be implemented for additional plantation and installation of solar on grid system at site.		

Remediation Plan

S. No.	Activity	Total Cost (CR)	Amount Spent (CR)
1.	Structural Cost	14.39	7.00
2.	Inside Fabrication System	16.84	0.20
3.	Ventilation System (Design &	14.39	0.50

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

	Installation)		
4.	Firefighting System (Installation & Water Storage Tank)	22.46	0.50
5.	Installation of Mechanical Multi Storage	19.65	0.25
6.	Other Development Cost Including Land, Water, Sewage, electricity & landscaping	378.26	1.50
Total		126.00	9.95

The project development cost Rs. 126 Crores has been estimated. The capital and the recurring expenditure on the item wise activities for environment management plan are as follows:

Description	Cost
Capital	8,47,91,220
Recurring (Operational Phase Maintenance Cost)	3,04,600
Total	8,50,95,820

PP, M/s Life Care Logistic Pvt. Ltd, Shri Vaibhav Rai, Director, 37 - 38, Lasudia Mori, Dewas Naka, A.B. Road, Dist. Indore has proposed to submit a guarantee of Rs. 11.75 lakh (including capital Rs. 7.7 Lakh and 4.045 Lakhs as recurring cost for this project) towards Remediation Plan. In addition, expenditure already incurred on implementation of EMP is Rs. 8,50,95,820/-. After presentation and discussions following information was asked to submit by the PP:

1. Revised plantation scheme with nos. as 5000 nos. & species with PP's commitment that the plantation shall be carried in association of forest department as suggested by the committee.
2. PP shall submit CA authenticated certificate wrt to remediation cost assessment.
3. Revised CER with enhanced appropriate budget including drinking water facility in the Pipilya Khedi village and distribution of Medical equipments in the nearby village's PHC (or need based after asking concerned doctor in the village PHC).
4. Carbon foot prints wrt vehicular movement.

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 जून 2022

5. PP's commitment that 20% power shall be solar based.
6. Address worst case scenario wrt MSW generation & their disposal.

PP submitted the reply on above issues vide letter dated 19/05/2022 and same was placed before the committee. Committee evaluated the reply and found satisfactory and acceptable and recommends that PP shall deposit the bank guarantee with three years validity of Rs. 11.75 Lakhs (equivalent to amount proposed in Remediation Plan /Restoration Plan) with the MP Pollution control Board after approval of the SEIAA as per the procedure laid down in the MoEF&CC Notification dated 08/03/2018.

Further, this being a violation case for which Ministry of Environment Forests & Climate Change vide its OM dated 28/01/2022, has reinstated the Standard Operating Process (SOP) dated 15/07/2021 as per the order dated 09/12/2021 of Hon'ble Supreme Court of India to deal with the violation cases. Penalty provisions as per para 12 (i) of the notification will be applicable i.e. 1% of the total project cost incurred upto date. PP has submitted a certificate on cost incurred of Rs. 9.95 Crore. As the operation has not started the penalty provision works out to be Rs. 9.95 lakh.

The EIA/EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of Environment Clearance for Development of Commercial Warehouse at Village - Pirkaradiya, Tehsil - Sawer, Dist. Indore, (MP). [Total plot area 1,30,780.00 sqm., Planning area 1,29,942.63 sqm., proposed built-up area 56,156.00 sqm.] subject to deposit bank guarantee of Rs. 11.75 Lakhs (equivalent to amount proposed in Remediation Plan /Restoration Plan) with the MP Pollution control Board after approval of the SEIAA, Penalty @ 1% of the total project cost incurred upto the date of filling of application i.e. Rs. 9.95 lakh as per clause 12 a.i. of MoEF&CC Notification dated 08/03/2018 and OM dated 07/07/21 and proof of credible action under section 15 read with section 19 of the Environmental (Protection) Act, 1986 as per clause 11, step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21 with following conditions:

I. Statutory compliance:

- i. The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project (if any).
- ii. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife (if applicable).
- iii. The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan & Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden. The

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 जून 2022

recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report. (in case of the presence of any schedule-I species in the study area) .

- iv. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee
- v. NOC shall be obtained from National Commission of Seismic Design Parameters (NCSDS) of CWC (if applicable).
- vi. Necessary approval of CEA shall be obtained for those projects having the project cost more than Rs. 1,000 crore (if applicable).

II. Air quality monitoring and preservation

- i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
- iv. Diesel power generating sets (1 x 125 + 1 x 160 + 2 x 62.5 + 1 x 20 + 1 x 25 KVA (DG Sets) proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
- v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

- prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
- vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
 - vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
 - viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
 - ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
 - x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
 - xi. The gaseous emission from DG set (1 x 125 + 1 x 160 + 2 x 62.5 + 1 x 20 + 1 x 25 KVA (DG Sets) shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
 - xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
- ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.
- iii. The total water requirement during construction phase are as follows :

S. No.	Particulars	Water Requirement	Wastewater Generation (KLD)	
			Quantity	Remarks

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 जून 2022

1	Domestic Water for workers (50 @ 45lpcd)	2.25	1.9125	85% Wastewater will be disposed into Septic Tank
2	Dust Suppression	2	1.6	Losses 20% loss on washing; rest will be collected and reused for curing after necessary treatment
3	Washing of Construction Equipment	2	2	-
4	Curing	2	2	Losses
Total		8.25 (KLD)	7.5125	-

iv. The total water requirement during operation phase are as follows

S. No.	Item Description	Number of Persons/Seats & Area	Water Requirement/ head (litres)	Total water Requirement (litres)
A	Fresh Water Requirement			
1	Staff	200	25	5000
2	Visitor	800	10	8000
Sub Total of A				13000
B	Flushing Water			
1	Staff	200	20	4000
2	Visitor	800	5	4000
Sub Total of B				8000
C	Treated Effluent Water Requirement - Misc. Uses			
1	Landscaping	5555.75	1/sqm	5555.75
Sub Total of C				5555.75
Total water requirement (A+B+C)				26555.75

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 जून 2022

Or says 26.55 say 27 KLD

- v. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be to monitor to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.
- vi. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
- vii. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.
- viii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
- ix. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
- x. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
- xi. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
- xii. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.
- xiii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fires water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 जून 2022

- water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.
- xiv. For rainwater harvesting, 09 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about 951m³/hr . Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.
 - xv. All recharge should be limited to shallow aquifer.
 - xvi. No ground water shall be used during construction phase of the project.
 - xvii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
 - xviii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring report.
 - xix. 19.05 KLD will be the total wastewater generated, which will be treated in the STP of 25 KLD. The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.
 - xx. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 25 KLD capacity and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.
 - xxi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
 - xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.
 - xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. Noise monitoring and prevention

- i. All the equipment likely to generate high noise shall be appropriately enclosed or inbuilt noise enclosures be provided so as to meet the ambient

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 16 जून 2022

noise standards as notified under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000, as amended in 2010 under the Environment Protection Act (EPA), 1986.

- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time .

V. Energy Conservation measures.

- i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

VI. Waste Management

- i. During the operation phase, waste is comprised of domestic as well as landscape waste. The solid waste generated from the project is mainly domestic waste and estimated quantity of the waste is approx. 170.27 kg per day (@ 0.15 kg per capita per day for the visitor, 0.25 kg per capita per day for the staff members, 0.2 kg per acres for landscape). Following arrangements has been made at the site in accordance with Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 and amended Rules, 2016 and the electronic waste is managed as per the guidance of E-waste (Management and Handling) Rules 2016.
- ii. Any additional muck generated from remaining activities, will be disposed off at nearby villages with due consent of local administration/gram panchayat. As the pipeline passes along the villages, villages will fall within 1-5 Km along the route of pipeline.
- iii. Solid waste management should be planned in details. Land filling of plastic waste shall be avoided and instead be used for various purposes as envisaged in the EIA/EMP reports. Efforts be made to avoid one time use of plastics.

VII. Green Cover

- i. Total 5000 trees (1000 plants in the project boundary & 4000 plants in the other areas as per submitted proposal) shall be planted as greenbelt

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

- development through CCF, Social Forestry or by concerned DFO or any technically competent agency in the first year.
- ii. Not tree can be felled/transplant.
 - iii. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should included plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover such as Pipal, ficus, Kadamb, Putranjeeva etc are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.
 - iv. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.
 - v. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

VIII. Transport

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
 - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
 - b. Traffic calming measures.
 - c. Proper design of entry and exit points.
 - d. Parking norms as per local regulation.
- ii. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
- iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. EMP & CER

- i. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

- iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
- v. PP has proposed 11.75 Lakh (including capital Rs. 7.7 Lakh and 4.045 Lakhs as recurring cost) for this project and PP, M/s Life Care Logistic Pvt. Ltd, Shri Vaibhav Rai, Director, 37 - 38, Lasudia Mori, Dewas Naka, A.B. Road, Dist. Indore has proposed to submit a guarantee with three years validity of Rs. 11.75 lakh towards Remediation Plan. In addition, expenditure already incurred on implementation of EMP is Rs. 8,50,95,820.00/-.
- vi. As per OM dated 07/07/21 Penalty @ 1% of the total project cost incurred upto the date of filling of application i.e. Rs. 9.95 lakh as per clause 12 that is of MoEF&CC Notification dated 08/03/2018 and OM dated 07/07/21 and proof of credible action under section 15 read with section 19 of the Environmental (Protection) Act, 1986 as per clause 11, step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.
- vii. For this project PP has proposed Rs 11.00 Lakh as Corporate Environment Responsibility (CER):

Nutritious food for nearby Aganwadi center	INR 2.0 lakhs
Drinking water facility for nearby areas	INR 2.0 lakhs
Provision for donation of medical equipment at nearby Public Health Centers (PHC) of near by areas.	INR 2.0 lakhs
Plantation as suggested by the registrar of Dr. B R Ambedkar University , Indore, MP.	INR 5.0 lakhs

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 जून 2022

XI. Human health issues

- i. Resettlement & Rehabilitation plan be implemented in consultation with the State Govt. as approved by the State Govt.
- ii. Budget provisions made for the community and social development plan including community welfare schemes shall be implemented in toto.
- iii. Preventive measures viz. fuming and spraying of mosquito control shall be done in and around the labour colonies, affected villages, stagnated pools, etc. Provisions be made to not to create any stagnated pools to avoid creation of breeding grounds of the vector borne diseases
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Labour force to be engaged for construction works shall be examined thoroughly and adequately treated before issuing them work permit. Medical facilities shall be provided at the construction sites.
- vi. Early Warning Telemetric system shall be installed in the upper catchment area of the project for advance intimation of flood forecast.
- vii. Emergency preparedness plan be made for any eventuality of the dam failure and shall be implemented as per the Dam Break Analysis.

XII. Miscellaneous

- i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
- iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention &

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 जून 2022

Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

The case was discussed in the 572nd SEIAA meeting dated 19/05/22 wherein certain observations are made by them and case is referred back to SEAC for re-appraisal vide letter no. 676-77/SEIAA/22 dated 06-06-22. The case was discussed in the meeting wherein it was deliberated that the case was appraised on the basis of information provided by the PP during presentation and documentary evidences provided such as damage assessment and remediation plan alongwith the certificate of CA. Since SEIAA has referred back this case for re-appraisal, committee decided to carryout the site visit for verification of facts submitted by PP by a committee member and based on the report, case shall be re-appraised in upcoming SEAC meetings.

15. Case No 9119/2022 Shri Jitendra Shroti, Owner, D-24, Vivek Vihar Colony, Lashkar Grid, Dist. Gwalior, MP - 474001 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.591 ha. (50,009 cum per annum) (Khasra No. 1974/2/Min-1, 2082), Village - Daurar, Tehsil - Ghatigaon, Dist. Gwalior (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1974/2/Min-1, 2082), Village - Daurar, Tehsil - Ghatigaon, Dist. Gwalior (MP) 2.591 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 29/04/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

आज दिनांक 06/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 9070 दिनांक 08/12/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर-पश्चिम दिशा में 325 मीटर पर आबादी तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में 130 मीटर पर प्राकृतिक नाला है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्ताव में गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 06/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन- 50,009 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 17.37 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 05.59 प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख :-

प्रस्तावित सी. ई. आर. गतिविधि

क्रमांक	सी. ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु में
1	ग्राम दौरार के आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण आहार का वितरण	30,000/-
2	ग्राम दौरार के स्कूल में छात्रों को खेल किट का वितरण	30,000/-
3	किसानों को गूगल पेड़ का वितरण और वृक्षारोपण व रखरखाव का प्रशिक्षण	15,000/-
4	ग्राम दौरार में महामारी में आवश्यक सावधानियों के लिए ग्रामीणों को स्वच्छता किट (हैंड सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स और नाक का मुखौटा) के रूप में वितरण और प्रशिक्षण	5,000/-
	Total	80,000/-

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3,000 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	नीम, खमेर, कचनार, शीशम, खैर, चिरोल आदि। (दो पंक्ति वृक्षारोपण)	1560
परिवहन मार्ग	नीम, खमेर, कचनार, आचार, अमलतास, शीशम, चिरोल, आंवला, पुत्ररनजीवा, मोलश्री आदि।	250
विद्यालय	नीम कचनार, महुआ, अचार अमलतास, गूगल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	250
आंगनवाड़ी	नीम, खमेर, चिरोल	940
	योग	3000

सेक की 569वीं बैठक दिनांक 06/05/22 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित कर सिया को भेजा गया था किंतु सिया की 726वीं बैठक 25/05/22 को प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदान श्री कल्याण श्रोती के नाम से 02.332 हे. की स्वीकृत दर्शाई है, इस बात की पुष्टि स्थल की गूगल इमेज से भी होती है । ऐसी स्थिति में संभवतः प्रकरण बी-1 श्रेणी में आयेगा । इस त्रुटि के सुधार हेतु प्रकरण वापिस सेक को परीक्षण हेतु भेजा जाये ।

समिति ने प्रकरण के अवलोकन किया और पाया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 9070 दिनांक 08/12/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 खदान कार्यरत है तथा उसको मिलाकर 500 मीटर की परिधि में कुल रकबा 04.923 हे. होता है किंतु सेक के कार्यवाही विवरण में लिपिकीय त्रुटिवश "अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है" टंकित हो गया है, जिसका सुधार किया जाना प्रस्तावित है, जो निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

"प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 9070 दिनांक 08/12/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 04.923 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है"।

उपरोक्तानुसार समिति ने पाया कि यदि 01 अन्य खदान का भी क्षेत्रफल (2.332 हे.) जोड़ दिया जाये तो भी दोनों खदानों को मिलाकर कुल रकबा 04.923 हे. होता है तथा खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

ही आयेगी । अतः उपरोक्त संशोधन के साथ समिति अपनी पूर्व की 569वीं बैठक दिनांक 06/05/22 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखती है ।

16. Case No 9137/2022 Shri Shiv Narayan Malviya, Owner, Village - Lagsari, Tehsil - Kukshi, Dist. Dhar, MP - 454001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (10000 cum per annum) (Khasra No. 196/1, 198, 197), Village - Undali, Tehsil - Kukshi, Dist. Dhar (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 196/1, 198, 197), Village - Undali, Tehsil - Kukshi, Dist. Dhar (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

सेक की 570वीं बैठक दिनांक 11/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 471 दिनांक 29/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 02 खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 4.50 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल पूर्व से खुदा हुआ है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया उनको खदान 03 फरवरी, 22 को आवंटित हुई है तथा आवंटन के पूर्व से ही यह क्षेत्र खुदा हुआ है, जिसका विवरण अनुमोदित माइन प्लॉन में दिया गया है जिसमें 21,264 घनमीटर पत्थर का उत्खनन हो चुका है तथा उसे सरफेस मैप पर भी दिखाया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्खनन हेतु लीज विद्यमान 02 पेड़ काटे जायेंगे तथा उनके एवज में 20 अतिरिक्त पेड़ उसी प्रजाति के लगाये जायेंगे । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के उत्तरी भाग से 10 मीटर की दूरी पर नाला निकल रहा है, अतः 40 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाये । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-17 में फ्लॉयड एश दिखाई गई है, इसके संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।
- ✓ खदान के उत्तरी भाग से 10 मीटर की दूरी पर नाला निकल रहा है, अतः 40 मीटर का सेट-बैक नॉन माइनिंग छोड़ा जाये ।
- ✓ लीज क्षेत्र में 02 पेड़ लगे हैं, जिन्हें काटा जाना प्रस्तावित किया गया है, अतः उसके एवज में उसी प्रजाति के 20 अतिरिक्त पेड़ों के साथ पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.एस.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 11/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन-10,000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.46 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.73 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.85 लाख :-

क्र.	प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु.)
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टाण्डा में मेडोनिक्स का इसीजी मशीन के साथ रिपोर्ट	50,000/-
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टाण्डा में गोदरेज का ए सी 1. 5 टन	35000/-
	कुल	85,000
संबंधित पी.एच.सी. में पदस्थ चिकित्सक के सुझाव अनुसार उपरोक्त इवेंट्री में परिवर्तन किया जा सकेगा ।		

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :

क्रमांक	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बेरियर ज़ोन	नीम, सीताफल, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू आदि।	250
2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल आदि ट्री गार्ड सहित ।	550
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	400
Total			1200

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

सिया की 726वीं बैठक दिनांक 25/05/22 में प्रकरण में 500 मीटर की परिधि में प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल खदानों का रकबा 5 हे. से अधिक हो रहा है, जिससे प्रस्तावित प्रकरण बी-1 श्रेणी में होना प्रतीत होता है । अतः उक्त प्रकरण को सेक को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

समिति ने प्रकरण के अवलोकन किया और पाया कि प्रकरण कि :

1. बी-1 श्रेणी का है या बी-2 श्रेणी का इसका निर्धारण सिया द्वारा ऑन लाईन आवेदन स्वीकार करते समय ही कर दिया जाता है तथा किसी भी परिस्थिति में सेक द्वारा श्रेणी परिवर्तन बी-1 से बी-2 या बी-2 से बी-1 नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बी-1 श्रेणी के प्रकरण आवेदन स्वीकार करने के उपरांत टॉर की श्रेणी में प्राप्त होते हैं । अतः सिया के पास उपलब्ध सभी संसाधनों के माध्यम से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन स्वीकार करते समय ही इस बात की अच्छी तरह से जाँच/परख करली जानी चाहिए कि प्रकरण बी-1 श्रेणी का है या बी-2 श्रेणी का । यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/अपलोडिड गूगल इमेज के अनुसार कोई भी संशय की स्थिति निर्मित हो रही हो तो इस बावत् स्पष्टीकरण (क्लेरीफिकेशन) संबंधित प्रधिकृत प्राधिकारी से प्राप्त कर ही आवेदन स्वीकार किये जाने चाहिए ताकि प्रकरणों का निपटारा निर्धारित समयावधि में हो सके एक बार आवेदन स्वीकार करने के पश्चात् यदि कोई भी श्रेणी परिवर्तन करना है तो स्वीकृत आवेदन को निरस्त कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः आवेदन किये जाने की स्थिति में ही श्रेणी परिवर्तन संभव है ।
2. प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि यह प्रकरण (क्रमांक 9137/2022) सिया द्वारा श्रेणी बी-2 में ही स्वीकार कर सेक को एप्राईजल हेतु भेजा गया था ।
3. समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) जिला धार, म.प्र. द्वारा जारी एकल प्रमाण पर विश्वास कर अपनी अनुशंसा की जिसके अनुसार (कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) जिला धार, म.प्र. द्वारा जारी एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 471 दिनांक 29/03/22 अनुसार) प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 02 खदान स्वीकृत है, जिनका रकबा क्रमशः 02.00 हे. एवं 1.50. हे. । इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर तीनों खदानों का कुल रकबा 4.50 हे. होता है ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान से उपरोक्त दोनों खदानों के अतिरिक्त एक अन्य खदान 500 मीटर की दूरी से अधिक दूर (लगभग 525 मीटर की दूरी) है ।
5. सेक द्वारा वर्तमान में सिया से वर्तमान निर्देशानुसार सभी आवेदनों का परीक्षण ऑनलाईन किया जा रहा है तथा ऑन लाईन परीक्षण में अभी यह सुविधा नहीं है कि क्या इसी खदान के आसपास पूर्व में किसी अन्य खदान को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई अथवा नहीं है। सेक द्वारा पत्र क्रमांक 33 दिनांक 25/2/22 (स्मरण पत्र क्रमांक 140 दिनांक

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

28/3/22) के माध्यम से संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल को पत्र लिख कर प्रदेश में स्वीकृत/प्रास्तावित खदानों की स्थिति दर्शाने वाला डिजिटाइज्ड मेप (500 मीटर में कल्सटर की स्थिति ज्ञात करने हेतु) चाहा गया था किंतु जो अभी तक अप्राप्त है ।

6. उपरोक्त से स्पष्ट है कि सेक द्वारा सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से जारी एकल प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर प्रकरण का परीक्षण कर अपनी अनुशंसाये सिया को प्रस्तुत की जाती है तथा अन्य कोई विकल्प (जैसे जिले का डिजिटाइज्ड मेप जिस पर सभी आवंटित/प्रस्तावित खदाने चिन्हाकित हों) समिति के पास उपलब्ध नहीं है। यदि सक्षम प्राधिकारी से ही गलत जानकारी प्राप्त हो तो यह स्थिति ठीक नहीं है तथा इसकी विस्तृत जाँच की जाना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे कई अन्य प्रकरणों में निर्णय इन्हीं प्रमाण-पत्रों के आधार पर दिया जाता रहा है ।

अतः सेक की अनुशंसा है कि यह उपरोक्त स्थिति / जानकारी संबंधित जिले के कलेक्टर के संज्ञान में लाई जाकर इसका पूर्ण परीक्षण/जाँच कराई जाये तथा यदि गलत प्रमाण पत्र जिला स्तर से जारी हुआ है यह प्रमाणित हो तो संबंधित पर उचित कार्यवाही की अनुशंसा की जाये ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो ।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 16 जून 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 16 जून 2022

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{\text{th}}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - f. Lease owner's Name, Contact details etc.

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 16 जून 2022

- g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - i. Minable Potential of sand mine.
 - j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - k. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
- i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 16 जून 2022

- a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - I. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - o. Minalable Potential of sand mine.
 - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - q. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Anganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माइनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साइड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 16 जून 2022

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for:
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

578वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabha of the villages in the area where project is proposed shall be obtained